

श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) : भगवान बुद्ध के समय से ही बिहार में एक जनपद था जिस का नाम था बज्जि । इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थी 'बज्जिका' । आज भी यह भाषा मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर एवं पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, सारण क्षेत्रों में लोक भाषा है । इस भाषा के बोलने वाले लगभग एक करोड़ हैं । इस भाषा की एक लिपि भी थी जो ब्रिटिश काल में कचहरी, दस्तावेज एवं पाठ्यक्रमों में प्रयुक्त होती थी । आज भी इस भाषा में दर्जनों पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हैं । किन्तु इस भाषा के प्रसार, प्रचार के लिए प्रोत्साहन देने की दिशा में पर्याप्त प्रयासों का सर्वथा अभाव रहा है । यहां तक बिहार की अन्य भाषाओं के समान इस भाषा को स्थान तक नहीं दिया गया । आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि पर भी इस भाषा को स्थान उपलब्ध नहीं है । इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि सरकार इस भाषा के समुचित उत्थान, प्रसार एवं प्रचार की दिशा में अग्रसर हो और प्रसार करे ।

(VI) NEED FOR WIDENING AND RAISING OF TUNNELS CONNECTING NORTHERN AND SOUTHERN SIDES OF ASANSOL.

SHRI SUSHIL BHATTACHARYA (Burdwan) : I would like to bring to the immediate notice of the Government the plight of the people who have to use the two tunnels connecting the northern side of Asansol with the southern. These tunnels are the only link roads for the people of several railway colonies and the inhabitants of Kasai Mohalla, old Kabatsthan and Jhinri Mohalla. The tunnels are almost as ancient as the Indian Railways and were built by the Britishers to extend the railway line from Raniganj to Asansol. Not only are they dilapidated but are so narrow and waterlogged that it is extremely difficult to cross the tunnels, trudging along waist deep mud during the monsoons. The schism between the fast enlarging slums in the outskirts of Asansol because of these waterlogged low lying

tunnels and the Asansol town with modern roads is not only posing problems of law and order but is creating a socially explosive situation. I, would, therefore, request the government to give the matter serious thought. If widening and raising the tunnels is not feasible, construction of a flyover seems to be the only alternative to put an end to the miseries of the people living in the area.

(VII) NEED FOR IMPROVING THE BOT OF GURJAR BAKHARWALAN IN JAMMU AND KASHMIR.

श्री राजेश पाहलट (भरतपुर) : उपाध्यक्ष जी, गुर्जर बखरवालान की स्थिति जम्मू और कश्मीर में बहुत दयनीय है । आर्थिक स्थिति इन लोगों की शुरू से ही खराब है । सरकार ने इनकी मदद के लिये जो भी कदम उठाये हैं वह भी पूरी तरह से इन लोगों तक नहीं पहुंचे हैं । जो पैसा केन्द्र सरकार ने इन लोगों के होस्टलों आदि में खर्च करने के लिये दिया था उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया । यहां तक कि जो बच्चे होस्टलों में रहते हैं उन बच्चों को मिलने वाली पूरी सुविधा नहीं दी गई ।

इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय भेड़ और बकरी चरा कर गुजारा करना है । अब तक न तो केन्द्र सरकार ने इस ओर कदम उठाया है और न ही राज्य सरकार ने । जो केन्द्र सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया है वह इस राज्य में लागू नहीं किया । इसके कारण यह लोग भूखे मर रहे हैं । मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि इसमें केन्द्र सरकार दखल दे । इस विषय में केन्द्र सरकार जल्दी कदम उठाये । यह वह बहादुर लोग हैं जिन्होंने देश के लिये 1965 व 1971 की लड़ाई में एक साधारण नागरिक होते हुए भी एक फौजी का रोल अदा किया । कई लोगों को सरकार ने बहादुरी के पुरस्कार दिये । इन सब चीजों के बावजूद भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । यह लोग देश के बार्डर पर हैं । वहां पर हमारे देश की नाजुक स्थिति रहती है । इनमें विश्वास कायम रखने के

लिये यह जरूरी है कि इसमें ठोस कदम उठाये जायें। मैडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों आदि प्रशिक्षण वाले संस्थानों में भी इन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(VIII) NEED FOR PROVIDING EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL IN THE FIELD OF EDUCATION.

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी-गढ़वाल) : उपाध्यक्ष जी, भारत में दिशामूलक शिक्षा के अभाव में 'प्रतिभा पलायन' की स्थिति निर्मित हो रही है। शासन में बैठे लोग भारतीयता के प्रति उपेक्षा की नजर रखते हैं, वे इस दुर्गति पर मौन हैं। सबसे अधिक असर बाल शिक्षा पर हुआ है। इसी कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था पूर्णतया दिशाहीन हो गई है। 35 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा ज्यादा हुई है। यह दुर्गति शहरी, कस्बाई और ग्रामीण स्तर पर मौजूद है। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विदेशी शिक्षा का एक प्रकार से आधिपत्य है। वहां न भारतीयता के मूल्य हैं न संस्कृति की शिक्षा जिसके परिणाम भी सरकार के सामने आये हैं।

देश का 35 प्रतिशत वह खेत मजदूर वर्ग जिसमें हरिजन, आदिवासी, छोटे किसान निहायत गरीब लोग आते हैं इन परिवारों के लोग बड़े किसानों एवं साहूकारों के यहां बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। इनके बच्चे विद्यालयों की सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाते। 40 प्रतिशत मध्य किसान ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पांचवी कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ा पाता है इसमें भी लड़कियों का प्रतिशत शून्य के बराबर ही होता है।

ग्रामीण भारत की 80 प्रतिशत गाड़ी कमाई का शहरों की चका चौंध पर सुविधा सम्पन्न विद्यालय निर्मित करने पर खर्च किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। पब्लिक स्कूलों में गरीब लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं इसलिये गरीब का लड़का आई.ए.एस. बनने तक की शिक्षा नहीं प्राप्त

कर सकता। प्राथमिक शिक्षा का मामला पूर्णतया उलझा दिया गया है, जो समग्र शिक्षा की आधारशिला थी, उसे चूर-चूर कर दिया गया है।

हमारी मांग है कि चाहे गरीब का लड़का हो चाहे अमीर का, स्कूल और शिक्षा दोनों की एक जैसी ही होनी चाहिये। सुविधाएं एक जैसी मिलनी चाहियें। शिक्षा के क्षेत्र में असमानता होगी, तो हर क्षेत्र में असमानता रहगी। यह लोक महत्व का मामला है, इस पर सरकार को अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिये।

MR. DEPUTY SPEAKER : The House stands adjourned to meet at 2.15 p.m.

13.12 hrs.

THE LOK SABHA ADJORNED FOR LUNCH TILL FIFTEEN MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK.

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT TWENTY MINUTES PAST-FOURTEEN OF THE CLOCK

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

CANTONMENTS AMENDMENT BILL—CONTD.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will now take up discussion and voting on the Cantonments (Amendment) Bill. Shri Harish Rawat-Absent. Acharya Bhagwan Dev.

The time allotted for this Bill is 3 hours. We have already exhausted 43 minutes. The time left is 2 hours and 17 minutes. If you all co-operate, we can complete this Bill today. I hope you will all extend your co-operation.